PROCEDURE FOR PRIVATISATION OF TELECOM DEPARTMENT

2511. SHRI N. GIRI PRASAD:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU-

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steps are being taken for privatisation of Telecom Services ;

(b) what procedure is being adopted by Telecom Department in relation to participation by Industry ; and

(c) whether these privatisation moves are being done at the behest of Multi-nationals, like Motorola and AT&T ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) ; (a) No Sir

(b) and (c) Does not arise.

स्टाफ क्वार्टर्स और भवनों का घटिया निर्माण

2512. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग की इमारतों और उसके स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण काफी घटिया किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में उप महानिदेशक (एस. आर.) के कार्यों की समीक्षा की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डाक विभाग में उप महानिदेशक (एस. आर.) का पद नहीं है ।

(ङ.) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक कर्मचारियों की हड़ताल

2513. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय डाक कर्मचारियों द्वारा की जा रही देश व्यापी हड़ताल को, जो पिछले तीन दिनों से चल रही है, समाप्त कराने के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है जिससे कि उपर्युक्त हड़ताल के कारण राष्ट्रीय सम्पत्ति को हो रही क्षति की पूर्ति की जा सके ;

(ख) क्या इस हड़ताल से भारत की सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक, वित्तीय और न्यायिक व्यवस्था नहीं चरमरा गई है ;

(ग) क्या हड़ताली डाक-कर्मचारियों की उचित मांगों को मानने में अनुचित सरकारी विलम्ब राष्ट्रहित के विरुद्ध है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार डाक-व्यवस्था को पुनरूज्जीवित करने के लिए नीति की घोषणा कब तक करने जा रही है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक कर्मचारियों तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों (ई डी ए) की हड़ताल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण दिनांक 10-12-93 को सायं 5 बजे समाप्त हो गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) डाक कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की कई मांगों पर संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे सी एम), अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की समिति और अन्य मंचों पर पहले ही विचार-विमर्श चल रहा था। हड़ताल से पूर्व ही कर्मचारियों की कई मांगें कर्मचारी महासंघों/संगठनों के साथ बातचीत के दौरान मान ली गई थीं ।

आश्वासन दिया गया था कि उनके मांग-पत्र की शेष मांगों पर भी तुरंत विचार या पुनर्विचार किया जाएगा। हड़ताल की धमकी के कारण डाक कर्मचारियों तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी मांगों को मान लेना जनहित में नहीं होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.टी.डी. बूथों का आबंटन

2514. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या संचार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस.टी.डी. बूथ केवल स्वस्थ उच्च वर्गीय और विकलांग व्यक्तियों को ही आबंटित किए गए हैं,

(ख) क्या इन बूथों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों अथवा पिछड़े वर्गों के गरीब नागरिकों को भी नियुक्त किया गया है,

(ग) क्या भारत के प्रत्येक शहर और गांव में घनी आबादी को देखते हुए ये बूथ अपर्याप्त हैं,

(घ) यदि हां तो सरकार समुचित, संतुलित, सर्वांगीण, न्याययुक्त तर्क-संगत ढंग से बूथों के आबंटन की प्रणाली कब तक बनाने का विचार रखती है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) पूर्ण नीति के अनुरूप एस.टी.डी., पी.सी.ओ, उच्च वर्ग, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों सहित उन सभी को उदारतापूर्वक आबंटित किए गए थे जो स्वेच्छा से इनका संचालन करने के लिए तैयार थे । वर्तमान नीति के अनुसार, एस.टी.डी, पी.सी.ओ, नेत्रहीनों, अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों तथा धर्मार्थ संस्थाओं सहित शिक्षित बेरोजगार, विशेषकर विकलांग व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) देश में एस.टी.डी, पी.सी.ओ. के तीव्र विस्तार को सुनिश्चित करने कि लिए, हाल ही में आबंटन प्रणाली में संशोधन किया गया है ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

देश में एस.टी.डी. सम्पर्कों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

2515. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के अंत तक देश में किन-किन स्थानों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ दिये जाने का प्रस्ताव है,

(ख) 1994 और 1995 के दौरान किन-किन स्थानों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या एस.टी.डी. सम्पर्क विस्तार का कार्य पूरी तरह से समय सारणी के अनुरूप चल रहा है, और

(घ) एस.टी.डी. नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) चालू वर्ष (1993-94) के अंत तक देश में जिन स्थानों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है, उनके नाम विवरण (नीचे देखिए) में दिए गए हैं।

(ख) 1994 और 1995 के दौरान जिन स्थानों को एस.टी.डी. से जोड़ने का प्रस्ताव है उनके नामों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) समय अनुसूची का पालन करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन ऐसा करना कतिपय वित्तीय दबावों और निधियों, भूमि, भवन और उपस्कर आदि जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(घ)—देश में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मौजूदा ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है ।